

सोबत मा. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई यांचे शैक्षणिक संस्था स्तरावर स्थापन करण्यात येणा-या तक्रार निवारण समितीमध्ये विद्यापिठ किंवा तंत्र शिक्षण संचालनालयाचा प्रतिनिधीच्या नामनिर्देशनाबाबतचे पत्र क्रमांक २/एनजीसी /तक्रार निवारण समिती/२०२३/७९७ दिनांक ५/९/२०२३ रोजीचे पत्र सोबत जोडलेले आहे. सदरहू पत्र व राजपत्र सोबत जोडलेली असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.

पृष्ठांकन क्र: तंशिविकाअ/शिक्षण/२०२३/2708
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती.
दिनांक. 28 SEP 2023

प्रति,

प्राचार्य, सर्व व्यावसायिक तांत्रिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था, अमरावती विभाग, अमरावती यांना माहिती व आवश्यक कार्यवाहीकरीता.



(मनोज म. अंधारे)

सहाय्यक संचालक (तांत्रिक)
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय
अमरावती.

प्रत :- प्रोग्रामर, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती यांना संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याकरीता.



महाराष्ट्र शासन

तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

३, महापालिका मार्ग, पत्र पेटी क्र. १९६७, मुंबई ४०० ००१.

दूरध्वनी क्र. ०२२-६८५९७४५०, ४४२, ४४३

ई-मेल — desk2@dtmaharashtra.gov.in वेबसाईट : http://www.dtmaharashtra.gov.in

क्र. २/एनजीसी/तक्रार निवारण समिती/२०२३/ ७९७,

दिनांक : 5 SEP 2023

प्रति,
सहसंचालक,
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,
अमरावती/औरंगाबाद/नागपूर/
नाशिक/पुणे/मुंबई

विषय : शैक्षणिक संस्था स्तरावर स्थापन करण्यात येणा-या तक्रार निवारण समितीमध्ये विद्यापीठ किंवा तंत्र शिक्षण संचालनालयाचा प्रतिनिधीच्या नामनिर्देशनाबाबत....

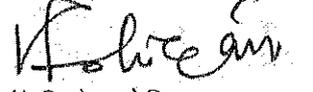
संदर्भ : ऑल इंडिया कौंसिल ऑफ टेक्नीकल एज्युकेशन (रिड्रेसल ऑफ फॅकल्टी/स्टाफ मॅम्बर) रेग्युलेशन, २०२१

तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नीत असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचेकडून सेवा विषयक बाबी संदर्भात या संचालनालयास तक्रारी प्राप्त होतात. या तक्रारी साधारणतः वेतन न मिळणे, वेतन कमी मिळणे, उपदान व रजारोखीकरण रक्कम न मिळणे, सेवापुस्तक, वेतन चिठ्ठी न मिळणे, आयकर प्रमाणपत्र न मिळणे, वरिष्ठांकडून त्रास, नोकरीतून काढून टाकणे इत्यादी स्वरूपाच्या असतात. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार विद्यापीठाशी संलग्नीत महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदभरतीस मान्यता, सेवाशर्ती, नियुक्तीस मान्यता, वित्तलब्धी, सेवानिवृत्तीलाभ व तद्अनुषंगिक इतर लाभ इ. बाबी विद्यापीठाच्या प्राधिकारात येतात. करीता यावरील तक्रारीबाबतची कार्यवाही सुध्दा विद्यापीठाच्या अधिकार कक्षेत येते.

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली च्या (Redressal of Grievance of Faculty/Staff Member) Regulation, २०२१, नुसार विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या महाविद्यालयामध्ये तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यास सूचित केले आहे. संदर्भीन अधिनियमामध्ये तक्रार निवारण समितीची रचना नमूद असून या समितीध्ये १ सदस्य विद्यापीठ किंवा तंत्र शिक्षण संचालनालयाने नामनिर्देशित केलेला आहे. संस्था स्तरावरील तक्रारींमध्ये बहुतांश तक्रारी कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे सेवाविषयक बाबीसंदर्भात असतात. सदर तक्रारींच्या मुळ मुद्यांबाबतचे नियम, तरतूदी या विद्यापीठाकडून अधिसूचित करण्यात येतात. तसेच तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अपिल विद्यापीठ व महाविद्यालयीन न्यायाधिकरणाकडे करण्यात येत असल्याने संस्था स्तरावरील तक्रार निवारण समितीमध्ये विद्यापीठ प्रतिनिधी असणे न्यायोचीत ठरेल. करीता, संस्थेच्या तक्रार निवारण समितीमध्ये विद्यापीठ प्रतिनिधी घेण्यास आपले स्तरावरून संस्थांना कळविण्यात यावे.

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण,
विभागीय कार्यालय, अमरावती
आवक क्र. २०५० दिनांक २०/०९

येथे असेही नमूद करण्यात येते की, आपल्या विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील संस्थांनी संदर्भिन अधिसूचनेद्वारे निर्देशित केलेली तक्रार निवारण समिती स्थापन केली आहे किंवा कसे? याबाबत आढावा आपले स्तरावरून घेण्यात यावा. आपण घेतलेल्या आढाव्यानुसार ज्या संस्थांनी संदर्भिन अधिसूचनेद्वारे निर्देशित केलेली तक्रार निवारण समिती गठित केली नसेल अशा संस्थांना सदर समिती गठित करण्यास आपले स्तरावरून सूचित करण्यात यावे. तसेच संस्थास्तरावरील तक्रार निवारण समितीने केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा नियमित त्रैमासिक आढावा आपले स्तरावरून घेण्यात यावा.



(डॉ. विनोद मोहितकर)

संचालक,

तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226122
CG-DL-E-25032021-226122

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119।
No. 119।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2021

फा. सं. 1-103/अभातशिप/पीजीआरसी/विनियम/2021.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :

- क. इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (संकाय/स्टॉफ सदस्यों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2021 है।
ख. ये विनियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10(ट) के अधीन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की गई अथवा अनुमोदित की गई सभी तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे।
ग. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य :

किसी भी संस्था में पहले से नियुक्त और साथ ही ऐसे संस्थान में नियुक्ति पाने की आकांक्षा रखने वाले संकाय/स्टॉफ सदस्यों की कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अक्सर प्रदान करना, इस संबंध में एक तंत्र स्थापित करना।

3. परिभाषा : इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) "अधिनियम" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 अभिप्रेत है ;
(ख) "परिषद्" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है ;
(ग) "यूजीसी" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

- (घ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा अथवा इसके अंतर्गत स्थापित अथवा शामिल संस्थाएँ हैं तथा जिसमें यूजीसी अधिनियम 1956 के खण्ड 3 के अंतर्गत घोषित की गई मानित विश्वविद्यालय संस्थाएँ भी शामिल हैं।
- (ङ) "राज्य" का अभिप्राय संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य से है जिसमें सघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं ;
- (च) "तकनीकी शिक्षा" से अभिप्रेत, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 2(छ) के अंतर्गत परिभाषित शिक्षा कार्यक्रमों से है।
- (छ) "तकनीकी संस्था" से अभिप्रेत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 की धारा 2(ज) के अंतर्गत परिभाषित संस्था से है।
- (ज) "पीडित संकाय/स्टॉफ सदस्य" से अभिप्रेत किसी ऐसे संकाय/स्टॉफ सदस्य से है, जिसे इन विनियमों के तहत परिभाषित शिकायतों के संबंध में किसी मामले अथवा तत्संबंधी किसी मामले में कोई शिकायत हो।
- (झ) "शिकायत" का अभिप्राय, और इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीडित संकाय/स्टॉफ सदस्य(यों) द्वारा की गई शिकायत(तें) शामिल हैं, नामतः—
- किसी संकाय/स्टॉफ सदस्य द्वारा ऐसे संस्थान में नियुक्ति लेने के प्रयोजन से जमा किए गए अपने किसी दस्तावेज जोकि डिग्री प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, अनुभव प्रमाणपत्र, कार्यमुक्ति आदेश अथवा किसी अन्य पुरस्कार के प्रमाणपत्र के रूप में अथवा अन्य दस्तावेज हों, को अपने पास रख लेना, या वापस करने से इंकार करना ;
 - सेवारत होने या सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र जैसा भी मामला हो, के दौरान वेतन/मजदूरी और/अथवा लाभ या किसी भी अन्य भत्ते या देय राशि आदि का भुगतान न करना ;
 - उनके वेतन और/अथवा लाभ तथा समान वेतन/पदनाम/अनुभव में अन्य स्टॉफ कर्मचारियों के बीच विसंगतियाँ ;
 - कोई कारण अथवा नोटिस अथवा ज्ञापन दिए बिना सेवा-समाप्ति ;
 - त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति पर लागू सरकार के नियमों के अनुसार अधिवर्षिता राशि का भुगतान न करना ; तथा
 - कोई अन्य देयता जो उनकी सेवा से सीधे जुड़ी हुई है और वित्तीय हानि या किसी नुकसान या आघात का कारण बनती है।
- (ञ) "शिकायत निवारण समिति" (जीआरसी) से अभिप्राय इन विनियमों के तहत गठित किसी समिति से है।
4. शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) :
- (i) सभी तकनीकी संस्थानों के लिए अनिवार्य है कि वे संस्थान स्तर पर ही सेवा मामलों सहित संकाय/स्टॉफ सदस्यों की शिकायत का समाधान करें। प्रत्येक संस्था द्वारा संकाय/स्टॉफ सदस्यों की शिकायत को देखने के लिए संकाय/स्टॉफ सदस्यों हेतु एक शिकायत निवारण समिति गठित की जाएगी। शिकायत निवारण समिति का संघटन निम्नानुसार होगा—
 - क. संस्थान के प्राचार्य — अध्यक्ष
 - ख. संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ प्रोफेसर — सदस्य के रूप में,
 - ग. राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशालय अथवा विश्वविद्यालय से एक कार्मिक (जिसे राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक/विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामांकित किया जाएगा) — सदस्य,
 - घ. एक वरिष्ठ संकाय सदस्य (जोकि एसोशिएट प्रोफेसर से नीचे के रैंक का ना हो) — सदस्य के रूप में।
 - (ii) पीडित संकाय/स्टॉफ सदस्यों द्वारा संस्थान के संबंध में की जाने वाली शिकायत, अध्यक्ष, शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) को संबोधित होनी चाहिए।
 - (iii) जीआरसी अपनी रिपोर्ट को अपनी सिफारिशों सहित, यदि कोई हों तो, के साथ शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक अथवा विश्वविद्यालय को भेजेगी तथा इसकी एक प्रति पीडित संकाय/स्टॉफ सदस्य को भी भेजी जाएगी।
 - (iv) यदि संकाय/स्टॉफ सदस्य शिकायत निवारण समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय/राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशालय से अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अपील कर सकते हैं।
5. विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर अथवा तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीई) स्तर पर गठित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ऐसी शिकायतों को देखेगा तथा मामले को राज्य/विश्वविद्यालय स्तर पर सुलझाएगा।
6. शिकायत निवारण समिति के बारे में जानकारी :
- संस्था को शिकायत निवारण समिति के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी जोकि इसके दायरे में आती है, को संस्था की वेबसाईट पर प्रमुखता से प्रस्तुत करना होगा।

प्रो. राजीव कुमार, सदस्य-सचिव

**ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd March, 2021

E. No. 1-103/AICTE/PGRC/Regulation/2021.—In exercise of the power conferred under clause (1) of Section 23 of the All India Council for Technical Education, Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following Regulations, namely:

1. SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT:

- a. These Regulations shall be called as the **All India Council for Technical Education (Redressal of Grievance of Faculty/Staff Member) Regulations, 2021.**
- b. They shall apply to all Technical Institutions recognized or approved by the All India Council for Technical Education as per Section 10(k) of the All India Council for Technical Education Act, 1987.
- c. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. OBJECTIVE:

To provide opportunities for redressal of certain grievances of Faculty/Staff Members already appointed in any institution, as well as those seeking appointment to such institutions, and a mechanism thereto.

3. DEFINITION: IN THESE REGULATIONS, UNLESS THE CONTEXT OTHERWISE REQUIRES:

- (a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987;
- (b) "Council" means the All India Council for Technical Education
- (c) "UGC" means University Grants Commission
- (d) "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act or State Act and includes an institution deemed to be university declared as such under section 3 of the UGC Act, 1956.
- (e) "State" means a State specified in the First Schedule to the Constitution of India and includes a Union territory;
- (f) "Technical Education" means programs of education as defined under section 2(g) of the All India Council for Technical Education, Act, 1987;
- (g) "Technical Institution" means an Institution as defined under section 2(h) of the All India Council for Technical Education, Act, 1987;
- (h) "aggrieved Faculty/Staff Member" means a Faculty & Staff Member, who has any complaint in the matters relating to or connected with the grievances defined under these Regulations.
- (i) "Grievance" means and includes, complaint(s) made by an aggrieved Faculty/Staff Member(s) in respect of the following service related matters namely:
 - i. withholding of, or refusal to return, any document in the form of certificates of degree, diploma, experience certificate, relieving order or any other award or other document deposited for the purpose of seeking appointment in such institution;
 - ii. non-payment of salaries/wages and/or benefits or any other allowances or dues etc. during services or retirement/resignation, as the case may be;
 - iii. Discrepancies between their wages and/or benefits and other members of staff in similar roles/post/experience.
 - iv. termination without giving any reason or notice or memorandum;
 - v. non-payment of gratuity amount as per prevailing Govt. rules in force on resignation/retirement; and

vi. any other liability which is directly connected with their service and causing financial loss or any harm or trauma.

(j) "Grievance Redressal Committee" means a Committee constituted under these Regulations;

4. GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE (GRC):

- (i) It is mandatory for all Technical Institutions to address the grievance of faculty/staff members including service matters at the Institution level itself. A Grievance Redressal Committee (GRC) for faculty/staff members shall be constituted by each Institution to look into the grievance of the faculty/staff members. The composition of the GRC shall be as follows:
 - a. Principal of the Institution as Chairperson
 - b. One Senior Professor of the affiliating University as a Member,
 - c. One Official from University or State DTE (Directorate of Technical Education) (to be nominated by DTE/University Vice Chancellor) as Member,
 - d. One Senior Faculty (not below Associate Professor) as Member.
 - (ii) A complaint from an aggrieved faculty/staff member relating to the institution shall be addressed to the Chairperson, Grievance Redressal Committee (GRC).
 - (iii) The GRC shall send its report with recommendations, if any, to the concerned DTE or University and a copy thereof to the aggrieved faculty/staff member, within a period of 15 days from the date of receipt of the complaint.
 - (iv) In case faculty/staff is not satisfied with the decision of Grievance Redressal Committee, they may appeal to the concerned affiliating University/State DTE (in case of diploma institutes) for redressal of their grievances.
5. The University level or DTE level Grievance Redressal Cell established by the University or DTE shall address such grievances and settle the matter at State/University level.

6. INFORMATION REGARDING GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE:

An institution shall furnish, prominently, on its website, all relevant information in respect of the Grievance Redressal Committee(s) coming in its purview.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member-Secy.

[ADVT -III/4/Exty./558/2020-21]